युवाओं को रोजगार के लिए एमएसएमई नीति में बदलाव की हो रही तैयारी

शहरों में कम चौड़ी सड़कों पर छोटे उद्योग की मिल सकती स्वीकृति

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) नीति में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों की तरह ही शहरी क्षेत्रों में भी सात मीटर चौड़ी सड़कों पर छोटे उद्योग लगाने की अनुमति दी जाएगी। इस संदर्भ में उच्च स्तर पर निर्णय लिया जा चुका है। एमएसएमई विभाग ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। उम्मीद है कि कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी जाएगी।

वर्तमान में राज्य में एमएसएमई की 96 लाख इकाइयां हैं। प्रदेश से होने वाले निर्यात में एमएसएमई की 46 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसीलिए सरकार एमएसएमई क्षेत्र को नए

औद्योगिक पार्कों को विकसित करने को अवस्थापना के नियमों में दी जाएगी ढील

सिरे से विकसित करने की तैयारी कर रही है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एमएसएमई क्षेत्र को और प्रोत्साहित करने के लिए सभी जिलों में 100-100 एकड़ में औद्योगिक व रोजगार पार्कों की स्थापना की योजना का शुभारंभ करेंगे। इन औद्योगिक पार्कों को स्थापित करने में समय लगेगा। इसलिए सरकार की कोशिश है कि नीति में संशोधन करके एमएसएमई क्षेत्र को और प्रोत्साहित किया जाए। वर्तमान में एमएसएमई इकाइयों में दो करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला है।

इसीलिए सरकार अब इस क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए सात मीटर चौड़ी सड़क पर उद्योग लगाने की अनुमित देने की तैयारी कर रही है। पहले 12 मीटर चौड़ी सड़क पर ही एमएसएमई उद्योग पार्क स्थापित किए जाते थे। इसके साथ ही छोटे औद्योगिक पार्कों को विकसित करने में अवस्थापना के नियमों में भी ढील दी जा सकती है। इनमें सीवरेज, चहारदीवारी, आंतरिक मार्ग, फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समय दिया जाएगा।